

नजीकरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कई समाजों में सार्वजनिक वस्तुओं का व्यापक रूप से नजीकरण मानवाधिकारों को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहा है और गरीबी में रहने वाले लोगों को और अधिक हाशिये पर ले जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विशेष संवाददाता फलिपि एल्स्टन ने अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत की।

- नजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नजी क्षेत्र तेज़ी से या पूरी तरह से सरकार द्वारा की गई गतिविधियों के लिये परंपरागत रूप से ज़िम्मेदार होता है, जिसमें मानव अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये कई उपाय किये जाते हैं।

मानवाधिकारों पर नजीकरण का प्रभाव

- नजीकरण का इसलिये समर्थन किया जाता है क्योंकि नजी क्षेत्र को अधिक कुशल, वृत्ति को संगठित करने में अधिक सक्षम, अधिक नवीन और अर्थव्यवस्था के पैमाने पर पूंजी निर्माण में सक्षम तथा लागत कम करने के रूप में देखा जाता है।
- हालाँकि, नेशनल ऑडिट ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम द्वारा किये गए अध्ययन में नषिकर्ष नकाला गया कि नजी वृत्ति मॉडल सार्वजनिक वृत्तिपोषण की तुलना में अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक आधारभूत संरचना प्रदान करने में अधिक महँगा और कम प्रभावशाली साबित हुआ।
- नजीकरण उन मान्यताओं पर आधारित है जो कि भूलभूत रूप से उन लोगों से अलग है जो गरमि और समानता जैसे मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं।
- लाभ ही इसका सर्वोपरि उद्देश्य है और समानता तथा गैर-भेदभाव जैसे विचारों को हटा दिया गया है।
- नजीकरण व्यवस्था मानव अधिकारों के लिये शायद ही कभी हतिकर रही है। गरीबी या कम आय वाले लोग नमिनलखित तरीकों से नजीकरण से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- आपराधिक न्याय प्रणाली का नजीकरण किया गया है, इसलिये गरीबों पर कई अलग-अलग शुल्क और जुरमाना लगाया जाता है।
- उन सेवाओं की गुणवत्ता जो वे प्राप्त कर सकते हैं, कम हो जाती है, साथ ही न्याय प्राप्त करने की उनकी संभावना भी कम हो जाती है।
- सामाजिक सुरक्षा के नजीकरण के परिणामस्वरूप अकसर गरीबों को एक नए और वृत्तीय रूप से कमज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन किया जाता है।
- समाज में श्रमिकों की समस्याओं का हल खोजने के लिये एक मॉडल प्रारूप को व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक चुनौतियों को पहचानने के लिये एक अन्य मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो कि आर्थिक दक्षता संबंधी चर्चाओं से प्रेरित होता है।
- बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ नजी प्रदाताओं के लिये सबसे आकर्षक हैं जहाँ महत्त्वपूर्ण उपयोगकर्ता शुल्क लिया जा सकता है और निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम होती है।
- लेकिन गरीब इस प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं कर पाते हैं इसलिये जल, स्वच्छता, बजिली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक और वृत्तीय सेवाओं जैसी अनेक सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं।
- सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का तेज़ी से नजीकरण किया जा रहा है, जो सेवा आउटसोर्सिंग, सोशल इंश्योरेंस, प्रशासनिक विकासकार का व्यावसायिकरण और अनुकूल परिणाम प्रदान करने में अग्रणी है।
- यह दृष्टिकोण नजी लाभकारी संस्थाओं को व्यक्तियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में दृढ़ संकल्पित करने के लिये सशक्त करता है।

अनुशंसाएँ

- रिपोर्ट में सफ़िराशि की गई है कि नजीकरण सदिधांत रूप में न तो अच्छा है और न ही बुरा लेकिन हाल के दशकों में जसि तरह से नजीकरण हुआ है, उसकी जाँच की जानी चाहिये। इसके लिये नमिनलखित कदम उठाए जाने चाहिये:
 - ◆ मानवाधिकार प्रभावों पर डेटा एकत्र और प्रकाशित किये जाने के लिये नजीकरण के साथ जुड़े सार्वजनिक और नजी क्षेत्र के भागीदारों द्वारा उचित मानकों को निर्धारित किया जाना चाहिये।
 - ◆ वशिष्ट क्षेत्रों तथा गरीब और हाशिये वाले समुदायों के मानवाधिकारों पर नजीकरण के प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिये।
 - ◆ संधियों, विशेष प्रक्रियाओं, क्षेत्रीय तंत्र तथा राष्ट्रीय संस्थानों के नए तरीकों का अन्वेषण किया जाना चाहिये जो नजीकरण के संदर्भ में उत्तरदायी रूप से राज्यों और नजी क्षेत्र को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं।

भारतीय संदर्भ में

- भारत में कई ऐसी सरकारी परियोजनाएँ हैं जो सार्वजनिक-नजी भागीदारी पर आधारित हैं।
- हाल ही में नीति आयोग ने सरकार द्वारा संचालित ज़िला अस्पतालों में गैर-संचारी रोगों (NCD) से निपटने के लिये सार्वजनिक-नजी साझेदारी (PPP) के लिये दृष्टि-निर्देश जारी किये हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट नीति आयोग को अपने दृष्टि-निर्देशों पर पुनर्विचार करने में मदद कर सकती है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/widespread-v-marginalises-the-poor-un-report>

